डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

# मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 अप्रैल, 2021, डिस्पेच दिनांक 16 अप्रैल, 2021

| वर्ष 64 | अंक 22 | भोपाल | 16 अप्रैल, 2021 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/– | आजीवन शुल्क 1500/– |

## प्रदेश के कृषि उत्पाद देश ही नहीं दुनिया में धूम मचायेंगे : मुख्यमंत्री

### आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश के लिए अर्थ–व्यवस्था और रोजगार पर केंद्रित मिशन अर्थ कार्यक्रम सम्पन्न

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना की कठिन परिस्थितियों में किसान की कर्मठता ही अर्थ–व्यवस्था का आधार बनी है। प्रदेश में पिछले साल हुए अनाज के भरपूर उत्पादन ने प्रदेश ही नहीं देश को मजबूती प्रदान की। राज्य सरकार किसान की आय को दोगुनी करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। खेती–पशुपालन–उद्यानिकी– मछली पालन–सहकारिता को समग्रता में लेकर फसलों के विविधीकरण, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और सही मार्केटिंग से हमारे प्रदेश के उत्पाद देश ही नहीं दुनिया में धूम मचायेंगे। मध्यप्रदेश सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री श्री चौहान मिंटो हाल में आयोजित राज्य स्तरीय मिशन अर्थ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मिशन अर्थ के अंतर्गत भदभदा भोपाल में 47 करोड़ 50 लाख रूपये की लागत से स्थापित देश की दूसरी अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला का डिजिटली लोकार्पण किया। कार्यक्रम में विभिन्न ग्राम पंचायतों में 260 करोड़ रूपये की लागत से बनी 985 सामुदायिक गौ–शालाओं का लोकार्पण और 50 करोड़ रूपये से बनने जा रही 145 सामुदायिक गौ शालाओं का शिलान्यास भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मिशन अर्थ कार्यक्रम में 33 विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण और चार उप केन्द्रों का भूमि पूजन भी किया। इनकी कुल लागत 1530 करोड़ रूपये है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में स्व–सहायता समूहों द्वारा उद्यानिकी रोपणियों में उत्पादित 80 लाख पौधे प्रदेशवासियों को समर्पित किये। इसके साथ ही किसान उत्पादक संगठन और कृषि अधोसंरचना निधि के हितग्राहियों को चेक भी वितरित किये।

कन्या पूजन और मध्यप्रदेश गान से आरंभ हुए इस कार्यक्रम में पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, उर्जा मंत्री श्री प्रद्युम सिंह तोमर, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह तथा विधायक श्री रामेश्वर शर्मा उपस्थित थे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम से सभी जिले डिजिटली जुड़े थे। भोपाल में स्थापित अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला पर लघु फिल्म का प्रस्तुतिकरण भी किया गया।

**गोबर शिल्प से बनी मूर्ति व पुस्तक भेंट**

मुख्यमंत्री श्री चौहान को पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल द्वारा गोबर से शिल्प से बनी मूर्ति तथा गोबर शिल्प से ही बनी पुस्तक "काऊ अवर अल्टीमेट सेवियर" भेंट की गई। इस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गोबर से ऐसे नवाचार सोच से परे हैं। इन गतिविधियों से लगता है कि हमारी गौ शालायें आत्म–निर्भर होंगी।

**कोरोना से सरकार और समाज को मिलकर लड़ना है**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण के विरूध लड़ाई राज्य सरकार और समाज को मिलकर लड़ना है। मास्क लगाने के नियम का गंभीरता से पालन करें, इसे किसी भी स्थिति में हल्के में न लें। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वप्रेरणा से टीकाकरण के लिए आगे आने की अपील की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अर्थ–व्यवस्था प्रभावित नहीं हो इसके लिए लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए आप सब का सहयोग आवश्यक है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

## मुख्यमंत्री श्री चौहान ने होली पर कृषकों को दी एक और नई सौगात

### कृषकों की खरीफ 2020 की ऋण देय की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 की गई

भोपाल रू सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया के अनुरोध पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खरीफ, 2020 के ऋणों की अदायगी के लिए अंतिम तिथि 28 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2021 कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अवधि बढ़ाकर प्रदेश के किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के कृषकों की खरीफ में सोयाबीन एवं अन्य फसलों का उत्पादन बिगड़ने के कारण कृषक 28 मार्च 2021 पर अपने खरीफ 2021 के ऋण की अदायगी करने में सक्षम नहीं थे। इससे अंतिम तिथि पर ऋण की अदायगी न होने के कारण कृषकों का ऋण वितरण से अंतिम तिथि पर 7 प्रतिशत तथा 28 मार्च 2021 से 13 प्रतिशत व्याज का भार आता। तिथि बढ़ जाने से किसानों को शून्य प्रतिशत पर ऋण सुविधा जारी रहेगी।

मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने प्रदेश के कृषक हितैषी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह के कृषकों की ओर से धन्यवाद व्यक्त किया है। श्री भदौरिया ने कृषक भाइयों से अपील की है कि वे अपने खरीफ ऋणों की अदायगी 30 अप्रैल 2021 के पूर्व जमा कर कालातीत होने से बचे और शासन की शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण का लाभ लेते हुए, अपनी समृद्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि करें।

## पहली बार गेहूं के साथ चना, मसूर, सरसों का हो रहा उपार्जन : मंत्री श्री पटेल

### देवास के संदलपुर में चना उपार्जन केन्द्र का किया शुभारंभ

**भोपाल।** किसान–कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश में पहली बार गेहूँ के साथ ही चना, मसूर और सरसों का उपार्जन किया जा रहा है। इससे किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सकेगा। श्री पटेल ने शनिवार को देवास जिले के संदलपुर में संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर और खातेगॉव विधायक श्री आशीष शर्मा के साथ चना उपार्जन केन्द्र का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री श्री पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि चना, मसूर और सरसों का उपार्जन गेहूँ के साथ होने से अब किसानों को अपनी उपज ओने–पौने दामों पर बेचने के लिये मजबूर नहीं होना पड़ेगा। फसल का बेहतर दाम मिलेगा, जिससे कि आत्म–निर्भर भारत और आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश अभियान के संकल्प एवं सपने को साकार करने में मदद मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिये सभी आवश्यक लाभकारी योजनाएँ बनाकर उन्हें लागू कर रहे हैं।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

# किसान हितैषी मुख्यमंत्री ने खोले विकास के द्वार : मंत्री श्री पटेल

## कृषक विश्राम–गृह–सह–प्रशिक्षण केन्द्र का किया भूमि–पूजन

**भोपाल।** किसान–कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़े किसान हितैषी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पुनः मुख्यमंत्री बनते ही विकास के द्वार खोल दिये हैं। प्रतिदिन विकास के नये काम प्रारंभ किये जा रहे हैं। मंत्री श्री पटेल भोपाल के साकेत नगर में 10 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले नवीन कृषक विश्राम–गृह–सह–प्रशिक्षण केन्द्र के भूमि–पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। भूमि–पूजन समारोह की अध्यक्षता विधायक श्रीमती कृष्णा गौर ने की।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों के लिये अत्याधुनिक कृषि तकनीक एवं उन्नत कृषि के लिये प्रशिक्षण केन्द्र–सह–विश्राम–गृह का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें उत्पादन के साथ ही अधिकतम लाभ अर्जन के लिये बेहतर विपणन के लिये भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि हमारी सरकार महात्मा गाँधी के स्वप्न को साकार कर रही है। गाँधी जी ने कहा था कि किसान इस देश की आत्मा और मूल रीढ़ हैं। किसान का विकास होगा, तो देश का विकास होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों एवं गाँवों का इतना विकास हो रहा है कि धीरे–धीरे गाँव और शहर का भेद खत्म हो रहा है। श्री पटेल ने कहा कि हमारी सरकारों द्वारा ऐसी नीतियाँ बनाई जा रही हैं, जिससे किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके। आत्म–निर्भर भारत और आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिये किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त कर आत्म–निर्भर बनाने के लिये सरकार दृढ़ संकल्पित है।

**गोविंदपुरा को मिली महत्वपूर्ण सौगात के लिये आभार**

विधायक श्रीमती कृष्णा गौर ने गोविंदपुरा क्षेत्र को मिली महत्वपूर्ण सौगात के लिये कृषि मंत्री श्री पटेल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री श्री पटेल ने भूमि–पूजन कर भाईदूज की अग्रिम भेंट दी है।

**31 हजार वर्ग फीट में बनेगा कृषक विश्राम–गृह**

एम्स हॉस्पिटल के पीछे अत्याधुनिक कृषक विश्राम–गृह–सह–प्रशिक्षण केन्द्र 31 हजार वर्ग फीट में बनाया जायेगा। यह भवन भू–तल के अतिरिक्त 3 मंजिला रहेगा। इसमें ऑडिटोरियम, कम्प्यूटर–रूम के अतिरिक्त 50 कृषकों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था रहेगी। भवन के बेसमेंट में 35 कारों के खड़े रहने का स्थान रहेगा। भवन की लागत 8 करोड़ 84 लाख रुपये होगी। फर्नीचर इत्यादि के लिये 2 करोड़ रुपये का प्रावधान पृथक से किया गया है। इस प्रकार भवन 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 18 माह में तैयार किया जायेगा। मंत्री श्री पटेल ने मण्डी बोर्ड के अधिकारियों को समयावधि में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने हिदायत भी दी है कि गुणवत्ता से समझौता करने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

इस अवसर पर मध्यप्रदेश वेयर–हाउसिंग कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष श्री सुधीर अग्रवाल, श्री केवल मिश्रा, श्री धर्मेन्द्र परिहार, श्री बारेलाल अहिरवार, पार्षद श्रीमती सीमा यादव और कृषक एवं अधिकारीगण मौजूद थे।

# अनुसूचित-जनजाति बस्ती विकास योजना में 7 कार्यों के लिए 1.66 करोड़ रु. मंजूरी

**भोपाल।** आयुक्त जन–जातीय कार्य विभाग ने अनुसूचित–जनजाति बस्ती विकास योजना में 7 कार्यों के लिये 1 करोड़ 66 लाख रूपये की मंजूरी प्रदान की है। यह मंजूरी उमरिया और सीहोर जिले में दी गई है।

उमरिया जिलें में मानपुर विकासखण्ड के 6 ग्रामों में सामुदायिक भवन निर्माण के लिये स्वीकृति दी गई है। यह सामुदायिक भवन 15 लाख रूपये प्रति भवन की लागत से तैयार किये जायेंगे। सीहोर जिले की ग्राम पंचायत सिंहपुर में बिजली व्यवस्था के लिये 76 लाख रूपये की मंजूरी दी गई है। निर्माण एजेंसियों को स्वीकृत किये गये कार्यों को गुणवत्ता के साथ नियत समय में पूरा किये जाने के निर्देश दिये गये है।

**खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते की दरों में संशोधन**

जन–जातीय कार्य विभाग ने वर्ष 2021–22 में विभागीय गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिये दैनिक भत्ते–भोजन की दरों में संशोधन किया है।

जिला एवं संभागीय स्तर की प्रतियोगिता में सहभागिता करने वाले खिलाड़ियों को 115 रूपये दैनिक भत्ता, विभागीय राज्य एवं शालेय शिक्षा स्तर प्रतियोगिता में सहभागिता करने वाले खिलाड़ियों को 130 रूपये और प्री–नेशनल कोचिंग केम्प में सहभागिता करने वाले खिलाड़ी को 200 रूपये दैनिक भत्ते की दर मंजूर की है। इस संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं।

# पथ विक्रेताओं के जीवन को आसान बनाना मेरी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

## ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने में मध्यप्रदेश अव्वल

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पथ– विक्रेताओं के जीवन को आसान बनाना मेरी प्राथमिकता में है। छोटा–मोटा व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स की खुशहाली और उनके जीवन के आधार को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि ऋण योजना का जिस गति से मध्यप्रदेश ने क्रियान्वयन सुनिश्चित किया, उससे मध्यप्रदेश देश में अव्वल स्थान पर है। इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्र के पथ व्यवसायियों के जीवन को आसान बनाने के लिये मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ–विक्रेता योजना प्रांरभ की गई, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे–छोटे स्ट्रीट वेण्डर्स को भी 10–10 हजार रूपये का ब्याज रहित ऋण उनके कार्य के उन्नयन के लिए दिलवाया गया है। क्रेडिट गारंटी राज्य शासन ने दी है। साथ ही ऋण प्रक्रिया को स्टाम्प ड्यूटी से भी मुक्त रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश के करीब साढ़े पाँच लाख शहरी एवं ग्रामीण पथ विक्रेताओं को प्रति हितग्राही 10 हजार रुपये की कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाई गई है।

**कठिन परिस्थितियों में मिला सहारा**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछले 6 माह इस योजना को प्राथमिकता में लेते हुए गति दी गई। वर्ष 2020 में जहाँ कोरोना संकट के कारण पूरी अर्थ–व्यवस्था के लिए मुश्किल के दिन थे। ये छोटे व्यवसायियों की आर्थिक कठिनाइयों का दौर भी था। ऐसी परिस्थितियों में कार्यशील पूँजी मिल जाने से जरूरतमंद पथ विक्रताओं को महत्वपूर्ण सहारा मिला। तब मध्यप्रदेश में करीब पाँच लाख पहचान–पत्र तैयार किए गए। ये काफी महत्वपूर्ण कार्य था। प्रदेश में अभियान संचालित कर छोटे कारोबारियों की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर्स को अपने जिले में पथ–विक्रताओं को पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर्ड करने के लिए कहा गया है। छूटे पथ–विक्रताओं का मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल पर पंजीयन करवाकर उनके ऋण बैंकों को प्रेषित करने के निर्देश है। साथ ही बैंकों से समन्वय कर प्रकरणों की स्वीकृति भी सुनिश्चित की जा रही हैं।

**नगरीय निकायों को सक्रिय भूमिका के निर्देश**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजना को गति देने के लिए सभी नगरीय निकायों को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

# हर व्यक्ति मास्क लगाए, इसके लिए सीख के साथ सख्ती भी जरूरी : मुख्यमंत्री

## मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मास्क लगाना आवश्यक है। हर व्यक्ति मास्क लगाए इसके लिए लोगों को सीख दिए जाने के साथ सख्ती भी जरूरी है। प्रदेश में सभी वर्गों के सहयोग से सघन जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। सभी माध्यमों से इसका प्रचार–प्रसार किया जाए। ऐसा माहौल बने कि हर व्यक्ति मास्क लगाने के लिए स्वतरू प्रेरित हो। साथ ही मास्क न लगाने पर जुर्माना लगाया जाए एवं कुछ समय के लिए ओपन जेल में भी रखा जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी जिलों में कोरोना के उपचार के लिए पर्याप्त संख्या में बेड्स की उपलब्धता के साथ ही प्रतिदिन इसकी जानकारी मीडिया, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से जनता को दी जाए। साथ ही वैक्सीनेशन संबंधी जानकारी भी दी जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा उपस्थित थे।

### गरीबों का निशुल्क इलाज सुनिश्चित हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक गरीब मरीज का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाए। उन्हें आयुष्मान कार्ड के आधार पर निःशुल्क चिकित्सा दें। साथ ही आवश्यकतानुसार जिन निजी अस्पतालों में बेड्स खाली हैं, उनके साथ अनुबंध कर बेड्स की संख्या बढ़ाएँ।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना आदि के संबंध में गलत तथ्य प्रकाशित/प्रसारित नहीं होने चाहिए। परंतु सही तथ्य प्रकाशित/प्रसारित होने पर तत्परता के साथ कार्रवाई की जाए।

### रविवार को भी होगा वैक्सीनेशन

जिन स्थानों पर रविवार को लॉकडाउन है, वहाँ रविवार को भी वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। बताया गया कि 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन लगवा सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगामी गणगोर आदि त्यौहार घर पर ही मनाएँ। सार्वजनिक रूप से त्यौहार मनाने तथा मेलों आदि की अनुमति नहीं होगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग होम आइसोलेशन संबंधी गाइडलाइन जारी करे। कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से इनकी निरंतर मॉनीटरिंग की जाए।

इंदौर जिले की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोरोना उपचार के लिए 10 हजार बैड्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। निजी अस्पताल कोरोना उपचार के लिए शासन द्वारा निर्धारित फीस ही लें, यह भी सुनिश्चित किया जाए।

### छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में हो इलाज की श्रेष्ठ व्यवस्था

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में कोरोना के उपचार की श्रेष्ठ व्यवस्था हो। महाराष्ट्र बॉर्डर सील किया जाए तथा गुड्स के वाहन, आवश्यक सेवाओं के वाहन और आपातकालीन आवागमन छोड़कर आवाजाही न हो।

### वैक्सीनशन की गति बढ़ाएँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीनशन की गति बढ़ाई जाए।

### उपार्जन केंद्रों का भी निरीक्षण करें प्रभारी अधिकारी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोरोना नियंत्रण के लिए जिलों के लिए नियुक्त प्रभारी अधिकारी अपने प्रभार के जिले में भ्रमण के दौरान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएँ देखें। उपार्जन केन्द्रों पर कोरोना संबंधी सभी सावधानियों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

### यह भी निर्देश दिए

- होम आइसोलेशन की सख्त मॉनिटरिंग की जाए। गाइडलाइन का पालन न करने पर कार्रवाई की जाए।
- जिन जिलों में अधिक संक्रमण है, वहाँ माइक्रो कंटेंटमेंट जोन बनाए जाएँ।
- कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट समय पर आ जाए।
- जिन जिलों में आवश्यकता हो कोविड केयर सेंटर्स बनाए जाएँ।
- जो जिले संडे लॉक डाउन की अनुमति चाहते हैं, उन्हें अनुमति दी जाए।
- फीवर क्लीनिक पर अच्छी व्यवस्था हो।
- ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण न फैले इस पर भी पूरा ध्यान दिया जाए।

# प्रशिक्षण प्राप्त कर किसानों को करें लाभान्वित : मंत्री श्री पटेल

## हण्डिया में एक दिवसीय कृषक मेला आयोजित

**भोपाल।** किसान–कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा जिले के हण्डिया की कृषक उपज मण्डी में आयोजित एक दिवसीय कृषक मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेस फॉर इनपुट डील्स (देसी) कोर्स की दो बैच का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने की।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर किसानों को लाभान्वित करें। एक दिवसीय कृषक मेले में प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के प्रति किसानों को जागरूक कर लाभान्वित करने के निर्देश कृषि मंत्री श्री पटेल ने दिये। संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के ऊर्जावान कृषि मंत्री कृषकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। श्री पटेल की हर पहल किसानों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने की होती है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में पहली बार चना, मसूर और सरसों का उपार्जन गेहूँ के साथ किया जा रहा है। इससे किसानों को निश्चित ही लाभ मिलेगा और उनकी उपज का ज्यादा से ज्यादा दाम प्राप्त हो सकेगा।

कृषक मेले में मंत्रीद्वय द्वारा कृषि विपणन पुरस्कार योजनांतर्गत ग्राम मझली के कृषक श्री विनोद रामचन्द्र को ट्रेक्टर की चाबी सौंपी गई। अन्य विजेताओं को चेक वितरित किये गये।

# प्रदेश की अनुसूचित जाति बस्तियों का विकास एवं विद्युतीकरण

## विकास कार्यों के लिये 17 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गयी

**भोपाल।** प्रदेश की अनुसूचित–जाति बाहुल्य बस्तियों के अधोसंरचानात्मक विकास के लिये संचालित योजना में सी.सी. रोड, नाली निर्माण, मंगल भवन, हैण्ड–पम्प खनन, पहुँच मार्ग, रपटा और पुलिया का निर्माण प्रमुख रूप से कराया जा रहा है। अनुसूचित–जाति बस्ती का चयन इस तरह से किया जाता है कि बस्ती में 40 प्रतिशत या उससे अधिक आबादी अनुसूचित–जाति वर्ग की हो।

इस योजना में इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर–2020 तक 40 कार्य स्वीकृत हुए। विगत वर्षों के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिये निर्माण एजेंसियों को करीब 17 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। योजना में पिछले वर्ष 2019–20 में 80 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था। इस राशि से अधोसंरचना से संबंधित 732 कार्यों पर 51 करोड़ की राशि व्यय की गई।

### सिंचाई स्रोत तक विद्युत लाइन का विस्तार

प्रदेश में लघु एवं सीमांत अनुसूचित–जाति वर्ग के किसान, जो अपने खेतों तक सिंचाई करने के लिये अपने सिंचाई स्रोत तक विद्युत लाइन लेने में असमर्थ होते हैं, उन्हें इस योजना में आर्थिक मदद दी जाती है। इस वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्व वर्षों में स्वीकृत अपूर्ण कार्यों के लिये 20 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें से करीब सवा 4 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। योजना में वर्ष 2019–20 में 40 करोड़ रुपये का प्रावधान था। इसमें सिंचाई कनेक्शन से जुड़े कामों के लिये 305 कार्यों को मंजूरी दी गई थी।

# दांडी यात्रा में शामिल होने का अवसर मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य

## मुख्यमंत्री श्री चौहान दांडी यात्रा के दौरान छापरभाटा (गुजरात) में ''आजादी का अमृत महोत्सव'' कार्यक्रम में शामिल हुए

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आजादी के 75 वें वर्ष में आयोजित इस दांडी यात्रा का संदेश है, आत्म–निर्भर भारत का निर्माण तथा उसके लिए हम सब का संकल्पबद्ध होना। यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, कि मुझे आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दांडी नमक सत्याग्रह की स्मृति में आयोजित, इस दांडी यात्रा में शामिल होने का अवसर मिल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई, सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश का एकीकरण किया और अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आत्म–निर्भर भारत का नव–निर्माण कर रहे हैं। आज हम सब इस दांडी यात्रा के माध्यम से आत्म–निर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लेते हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज दांडी यात्रा के दौरान, गुजरात के सूरत जिले के छापरभाटा गाँव में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर गुजरात के वन एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रमण लाल पाटकर, सांसद श्रीमती दर्शना बेन आदि उपस्थित थे।

### नमक प्रतीक है वफादारी का, देशभक्ति का और आत्म–निर्भरता का

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था और 5 अप्रैल को दांडी नवसारी पहुँचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर, अंग्रेज शासन द्वारा नमक पर लगाए गए प्रतिबंध को तोड़ दिया था। नमक प्रतीक है वफादारी का, देशभक्ति का तथा आज के संदर्भ में, यह

प्रतीक है, आत्म–निर्भरता का। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उस समय गांधी जी ने दांडी यात्रा के माध्यम से देश को आजाद करने का संकल्प लिया था, आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित दांडी यात्रा के माध्यम से हम संकल्प ले रहे हैं, आत्म–निर्भर भारत के निर्माण का।

### विश्व के हजार वर्ष के इतिहास में गांधी जैसा व्यक्तित्व नहीं हुआ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विश्व के एक हजार वर्ष के इतिहास में महात्मा गांधी जी जैसा व्यक्तित्व पैदा नहीं हुआ है, जिन्होंने अहिंसा के पथ पर चलकर देश को आजादी दिलवाई। हमें अंग्रेजों से आजादी आसानी से नहीं मिल गई। एक और गांधीजी का अहिंसक आंदोलन था, वहीं दूसरी ओर हजारों क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए हँसते–हँसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

### आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश के लिए तेजी से कार्य

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्म–निर्भर भारत के निर्माण की घोषणा की थी, उसी दिन से मध्यप्रदेश में आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण पर तेजी से कार्य हो रहा है। सबसे पहले राज्य में इसका विकास रोड मैप बनाया गया, अब उस पर तत्परता के साथ अमल किया जा रहा है। आत्म–निर्भर भारत, हमारे लिए मंत्र है। हम पूरी कर्त्तव्यनिष्ठा, मेहनत एवं समर्पण के साथ इसे चरितार्थ करेंगे।

### गुजरात ने देश को महान सपूत दिए

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गुजरात ने देश को महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल और श्री नरेंद्र मोदी जैसे महान सपूत दिए हैं।

### मध्यप्रदेश एवं गुजरात को दिलों से जोड़ती हैं ताप्ती और नर्मदा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गुजरात यात्रा के दौरान आज प्रातः माँ नर्मदा एवं माँ ताप्ती का दर्शन एवं पूजन किया। दोनों नदियाँ मध्यप्रदेश से निकलती हैं, मध्यप्रदेश एवं गुजरात में प्रवाहित होती हैं और दोनों राज्यों को दिलों से जोड़ती हैं।

# लक्ष्य से 100 करोड़ रू. अधिक का किया संग्रहण : मंत्री श्री राजपूत

## परिवहन मंत्री ने उपलब्धि को बताया टीम वर्क, दी बधाई

**भोपाल।** परिवहन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में राजस्व प्राप्ति के लिए निर्धारित लक्ष्य 2640 करोड़ रूपये के विरूद्ध 2745 करोड़ रूपये की राशि राजस्व के रूप में अर्जित की गई, जो निर्धारित लक्ष्य से 105 करोड़ रूपये अधिक है। परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि विभाग ने निर्धारित लक्ष्य 2640 करोड़ रूपये 23 मार्च 2021 को ही प्राप्त कर लिया था।

परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि यह उपलब्धि कोरोना संक्रमण काल की वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए रिकार्ड राजस्व का संग्रहण मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कोरोनो काल में आम जनता की परेशानियों को हल करने के साथ हुए राजस्व लक्ष्य से अधिक की प्राप्ति निःसंदेह परिवहन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कर्मठता का ही परिणाम है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

परिवहन आयुक्त श्री मुकेश जैन ने बताया कि राजस्व संग्रहण के लिए पथ भ्रष्ट वाहनों पर छूट एवं एक मुश्त भुगतान की सरल समाधान योजना की मॉनीटरिंग प्रति सप्ताह की जाती रही। सभी जिलों को माह के प्रारंभ में ही बकाया कर वाले वाहनों की सूची उपलब्ध कराकर उनसे राजस्व प्राप्ति के लिए निर्देशित किया गया। मंत्री श्री राजपूत के निर्देशानुसार एक योजना बनाकर क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों, चेक पोस्ट प्रभारियों एवं सुरक्षा स्कवॉड के मध्य सामूहिक चेकिंग का कार्य किया गया।

अपर परिवहन आयुक्त श्री अरविन्द सक्सेना द्वारा प्रवर्तन अमले द्वारा सघन चेकिंग कर बकाया कर से संबंधित चिन्हित वाहनों से वसूली की कार्यवाही की गई। विशेषकर उद्योगों में संबद्ध ऐसे वाहन जिन पर कर की राशि बकाया थी, को समय–समय पर चेक कर उनसे वसूली की गई। लॉकडाउन अविध के बाद पूरे प्रदेश में सरेंडर बसों का नियमित संचालन प्रारंभ किया गया। इसके साथ ही अन्य राज्यों को जारी किए जाने वाले परमिटों के नवीनीकरण द्वारा अंतरराज्यीय बस सेवाओं को सामान्य एवं नियमित करने से राजस्व आय में वृद्धि के प्रयास तेज किये गये।

श्री सक्सेना ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के प्रथम 5 माह 15 अगस्त तक भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन 30 से 40 प्रतिशत रहने से त्रैमासिक कर में भारी गिरावट हुई है। सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में विभिन्न परिवहन दस्तावेजों का नवीनीकरण माफ होने से राजस्व प्राप्ति में कमी आई थी। इसके बावजूद भी विभाग द्वारा 105 करोड़ रूपये से अधिक राजस्व प्राप्ति उल्लेखनीय है।

अपर परिवहन आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश के रतलाम, शिवपुरी, मंदसौर, भोपाल, उज्जैन, गुना, ग्वालियर, सीधी, बैतूल, अशोक नगर, जबलपुर, कटनी, दमोह, शहडोल, छिन्दवाड़ा, मंडला, इंदौर और सिंगरोली परिवहन कार्यालयों द्वारा आवंटित राजस्व लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त किया गया।

# किसान चिंतित न हों नुकसान की भरपाई सरकार करेगी : राजस्व मंत्री

## सभी कलेक्टर को तदाशय का पत्र भेजे जाने के दिए निर्देश

**भोपाल।** राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि आग या प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान होने पर किसान बिल्कुल भी चिंता न करें। क्षतिग्रस्त फसल के एक–एक दाने की भरपाई सरकार करेगी। प्रदेश सरकार किसानों कि हर मुसीबत में उनके साथ है। उन्होंने इस मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को पत्र जारी करने के निर्देश प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी को दिए हैं। मंत्री श्री राजपूत रायसेन के बाड़ी–बरेली एवं जैसीनगर सागर के ग्रामों में विगत दिनों खड़ी फसलों में आग लग जाने से पीड़ित किसानों से मिले और उन्हें धीरज बँधाया।

राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि अनेक मामलों में शॉर्ट–सर्किट या अन्य कारणों से दुर्घटनावश फसलें आग लग जाने के कारण नष्ट हो जाती हैं। फसल कटाई के समय ऐन वक्त पर हुए नुकसान से किसानों की रात–दिन की मेहनत और भविष्य की उम्मीदें समाप्त हो जाती हैं। फसलों में आगजनी की घटनाओं के बाद किसानों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था तब कहीं मुआवजे की राशि उन्हें मिल पाती थी।

उन्होंने कहा कि अब किसानों को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है, ऐसी अचानक आई प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी प्रकार की दुर्घटना से फसल नष्ट हो जाने पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार नुकसान का आंकलन कर तुरंत भरपाई करेगी। राजस्व मंत्री के रूप में मैं यह कह सकता हूँ कि क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया को अब बहुत सरल और सहज कर दिया गया है।

मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि अब किसानों को आगजनी की घटनाओं पर भटकना नहीं पड़ेगा। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके का मुआयना करके प्रकरण बनाएंगे, जिस पर तुरंत मुआवजे का भुगतान किया जायेगा।

## जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह ने विकास कार्यों का किया भूमि–पूजन

**भोपाल।** जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही हर परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जायेगा। जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह आज उमरिया जिले के पाली जनपद के ग्राम कुनकुनी में 15.74 लाख रूपये लागत के सीसी रोड और पुलिया निर्माण के भूमि पूजन के बाद ग्रामीणों को संबोधित कर रही थी।

# आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में औद्योगिक क्षेत्र की एक साल की उपलब्धियाँ

मुख्यमंत्री के रूप में श्री शिवराज सिंह चौहान की देशभर में एक अलग पहचान है। उन्होंने पद की गरिमा को गौरवान्वित किया है। अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश के अग्रणी रहने का श्रेय भी आज उन्हें दिया जा सकता है। सच्चाई यह है कि मध्यप्रदेश और श्री शिवराज सिंह चौहान एक–दूसरे की पहचान बन गए हैं। मध्यप्रदेश के गठन के बाद जनता के कल्याण के लिए सबसे अधिक अवधि के मुख्यमंत्री ही नहीं जनता के मुख्यमंत्री के तौर पर भी श्री चौहान की छवि बनी है। उन्होंने हर कार्यकाल में यादगार कार्य किए हैं।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में प्रदेश को अग्रणी बनाकर आगामी तीन वर्षों में आत्म–निर्भर बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिये आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश रोडमेप–2023 तैयार किया गया है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा किए गए प्रयासों की पिछले एक साल की अनेक उपलब्धियाँ हैं।

**नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना**

प्रदेश के विभिन्न अंचलों में मांग के अनुरूप 1575 से अधिक हेक्टेयर भूमि पर 20 नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से प्रदेश में लगभग 15 हजार करोड़ रूपये के निवेश के साथ 10 हजार व्यक्तियों को रोजगार भी मिल सकेगा।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में 5 औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 1 हजार 325 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का विकास कार्य पूर्ण किया गया। साथ ही 6 विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों में 1 हजार 323 हेक्टेयर क्षेत्रफल में भी उन्नयन कार्य पूर्ण किया गया है। इससे औद्योगिक इकाइयों को विकसित अधोसंरचना प्राप्त होने के साथ ही प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

**अटल बिहारी बाजपेयी प्रोग्रेस–वे**

यह 400 किलोमीटर का राजमार्ग श्योपुर जिले को राजस्थान के कोटा से जोड़ेगा। यह राजमार्ग प्रदेश के श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों से होकर गुजरेगा। इस प्रोग्रेस–वे के साथ 5 औद्योगिक केन्द्र विकसित करने के लिये कन्सलटेंट की नियुक्ति की गई है। इसी तरह नर्मदा एक्सप्रेस–वे के दोनों तरफ भी इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास किया जाएगा।

**लैण्ड पूलिंग योजना**

योजना में इन्वेस्टमेंट रीजन पीथमपुर जिला– धार के औद्योगिक क्षेत्र 4 एवं 5 के विकास के लिये प्रथम चरण में 586 हेक्टेयर भूमि पर 550 करोड़ रूपये का व्यय कर औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। इससे क्षेत्र में 15 हजार करोड़ रूपये का निवेश एवं 10 हजार व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना संभावित है।

**बल्क ड्रग्स/मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना**

भारत सरकार की फार्मा प्रोत्साहन नीति में औद्योगिक क्षेत्र मोहासा– बाबई जिला होशंगाबाद में 2074.16 एकड़ भूमि पर बल्क ड्रग्स पार्क तथा 358 एकड़ से ज्यादा भूमि पर मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है।

कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑक्सीजन/मेडिकल गैसेस निर्माण क्षेत्र में प्रदेश को आत्म–निर्भर बनाने के लिये औद्योगिक क्षेत्र मोहासा– बाबई जिला होशंगाबाद में ऑक्सीजन/मेडिकल गैसेस निर्माण इकाई की स्थापना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।

**वोकल फॉर लोकल के मजबूत रास्ते**

**एक जिला एक उत्पाद :** स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी ब्राण्डिंग तथा विपणन हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले का एक विशिष्ट उत्पाद चिन्हित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस संकल्प पर अमल के लिये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन्टेलीजेन्स तथा निर्यात सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिये कन्सल्टेंट का चयन किया गया है।

**इन्वेस्ट एमपी ब्राण्ड स्थापित करना**

प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिये "इन्वेस्टमेंट ड्राइव" निर्बाध रूप से चल रही है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न रोड–शो, वर्चुअल ईवेंट्स, प्रदर्शनी आयोजित किये जा रहे हैं। इन आयोजनों में निवेशकों से सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश को निवेश के लिये आकर्षक राज्य के रूप में प्रोजेक्ट करने उपलब्ध निवेश की संभावनाओं की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के उद्देश्य से वर्ष 2020–21 में दो वर्चुअल राउण्ड टेबल चर्चाएँ, दो अंतर्देशीय ईवेंट्स तथा एक अंतर्राष्ट्रीय ईवेंट में भागीदारी/आयोजन किया गया। विभाग के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न वेबिनार, वीडियो कॉन्फ्रेन्स, वर्चुअल इवेंटस् में भागीदारी कर निवेशकों से सम्पर्क स्थापित किया गया।

**अन्य महत्वपूर्ण योजना**

कोविड–19 के दौरान भी पिछले एक वर्ष में प्रदेश में 7 बड़े उद्योग स्थापित हुए। इनमें लगभग 1563 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश एवं 5705 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।

औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणी की 372 इकाइयों को 251 हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटित की गयी। इनमें लगभग 4336 करोड़ 82 लाख रूपये का पूँजी निवेश तथा 12 हजार 509 व्यक्तियों को रोजगार संभावित है।

**औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता**

इस एक साल में उद्योग संवर्धन नीति–2019 (संशोधित–2020) में प्रावधानित सुविधाओं यथा वैट/सीएसटी प्रतिपूर्ति सहायता निवेश प्रोत्साहन योजना, ब्याज अनुदान, ईटीपी, एसटीपी, अधोसंरचना विकास इत्यादि के अन्तर्गत वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को राशि 387 करोड़ 55 लाख रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

कोविड–19 से बचाव के लिये प्रदेश के नागरिकों को अधिकाधिक संख्या एवं कम कीमत में मास्क उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की महिला उद्यमियों के रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से जीवन शक्ति योजना लागू की गई।

**नीतिगत निर्णय**

मध्यप्रदेश सरकार ने कोविड–19 संकट के कारण उद्योगों को आ रही कठिनाइयों को देखते हुए उद्योग नीति एवं भूमि आवंटन नियम के अंतर्गत विशेष रियायत/समयावधि में छूट प्रदान की। परिधान क्षेत्र में 25 करोड़ रूपये से अधिक पूँजी निवेश की विनिर्माण इकाइयों को मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई मान्य करने का निर्णय भी लिया गया है।

इस साल निवेश संवर्धन पर मंत्रि–परिषद समिति द्वारा भी 631 करोड़ 60 लाख रूपये के पूँजी निवेश वाले चार परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं में करीब सवा 5 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा।

**ईज ऑफ डूइंग बिजनेस**

प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग–2019 में देश में चौथी रैंक अर्जित की है। भारत सरकार द्वारा व्यापार संचालन सरलीकरण के लिए राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय व्यापार सुधार कार्यक्रम–2020 के क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के आवश्यक निरीक्षणों के लिए कम्प्यूटराइज्ड केन्द्रीकृत निरीक्षण व्यवस्था विकसित एवं परिनियोजित की गयी है। अपने उद्योग के क्रियान्वयन को प्रारंभ करने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न विभागों की सम्मतियाँ/अनुमतियाँ 30 दिवस के अन्दर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। निगम के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन से संबंधित कई सेवाओं को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 में अधिसूचित किया गया है।

इसी तरह निवेशकों द्वारा ऑनलाइन अभ्यावेदन में प्लॉट, मशीनरी, शेड एवं बिल्डिंग में संयुक्त रूप से 10 करोड़ की राशि के बराबर अथवा उससे अधिक निवेश प्रस्तावित करने की स्थिति में पदाभिहित पोर्टल द्वारा आशय–पत्र उसी दिवस में स्वतः जारी किया जाएगा। निवेशकों द्वारा ऑनलाइन अभ्यावेदन में प्लॉट एवं मशीनरी, शेड एवं बिल्डिंग में संयुक्त रूप से 10 करोड़ रूपये से कम राशि का निवेश प्रस्तावित करने की स्थिति में आवश्यक रूप से 7 दिवस में आशय–पत्र जारी कर दिया जाएगा। सात दिवस में आशय–पत्र जारी नहीं करने की दशा में मान्य अनुमोदन पदाभिहित पोर्टल द्वारा जारी किया जाएगा। आशय–पत्र की पूर्ण राशि प्राप्त होने की तारीख से 4 दिवस में आवंटन आदेश जारी हो जाएगा। समयावधि में आवंटन आदेश जारी न करने की दशा में मान्य अनुमोदन पदाभिहित पोर्टल द्वारा जारी किया जाएगा। पट्टा अभिलेख के पंजीयन होने के बाद 3 दिवस में आधिपत्य दिया जायेगा। समयावधि में आधिपत्य प्रदान न करने की दशा में मान्य अनुमोदन पदाभिहित पोर्टल द्वारा जारी होगा।

# मृगनयनी एम.पी. गवर्नमेंट के उत्पाद अब अमेजन.इन पर भी

**भोपाल।** अमेजन.इन मृगनयनी एम.पी गवर्नमेंट एंपोरियम कोलकाता के साथ सहयोग कर प्रदेश के पाँच हजार से ज्यादा बुनकरों को अमेजन भारत में अपने ग्राहकों तक पहुँचाने में मदद करेगा। यह घोषणा अमेज़न.इन के फ्लैगशिप 'कारीगर' प्रोग्राम के तहत अपने मार्केट प्लेस पर मृगनयनी एम.पी. गवर्नमेंट. एंपोरियम को लॉन्च कर की है।

इस लॉन्च अमेज़न.इन द्वारा मध्यप्रदेश के बुनकरों को ग्राहकों तक अपने क्षेत्र के विशेष उत्पाद प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। इससे बुनकरों के जीवन एवं व्यवसायों को लाभ मिलेगा। यह अभियान डिजिटल समावेशन को बढ़ाने एवं बुनकर समुदाय को सशक्त बनाने के लिए चलाया गया है, जिससे उनके लिए आर्थिक अवसरों का निर्माण हो और स्थानीय उद्यमशीलता एवं रोजगार सृजन करने में मदद मिले।

मृगनयनी एम.पी.गवर्नमेंट एंपोरियम कोलकाता के विक्रेताओं को कारीगर प्रोग्राम के तहत डिस्काउंटेड रेफरल शुल्क, शिपिंग, उत्पाद की डिलीवरी का सहयोग, इमेजिंग एवं मार्केटिंग सपोर्ट, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यवसाय एवं सेल्स का सपोर्ट दिया जाएगा। इस सहयोग से बुनकरों के ग्राहक आधार का विस्तार होगा और उनके काम को विस्तृत पहचान मिलेगी। मृगनयनी एम.पी. गवर्नमेंट एंपोरियम कोलकाता लगभग 1000 उत्पादों के संग्रह के साथ मार्केटप्लेस में शुरू होगा। देश में अमेज़न.इन के लाखों ग्राहक इन विक्रेताओं से चंदेरी, महेश्वरी, तुसार साड़ी, ड्रेस सामग्री, फर्नीशिंग, हैंडीक्रॉफ्ट्स, ज्वेलरी एवं गिफ्ट सामग्री के रूप में विविध तरह के अद्वितीय उत्पाद खरीद सकेंगे।

डायरेक्टर एमएसएमई एवं सेलिंग पार्टनर एक्सपीरियंस अमेजन इंडिया ने कहा कि हमारा उद्देश्य कारीगरों एवं बुनकरों की वृद्धि करना है। हम भारतीय क्रॉफ्ट्स के हर रूप को ऑनलाइन लाने के मिशन पर काम कर रहे हैं और ग्राहकों के लिए उत्पाद श्रृंखला का विस्तार कर रहे हैं।

# मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए मास्टर प्लान तैयार करें : मंत्री श्री पटेल

## मंडी बोर्ड के तकनीकी संभाग और कार्यपालन यंत्रियों की बैठक सम्पन्न

**भोपाल।** किसान–कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मंडियों को स्मार्ट बनाने की कार्य–योजना के साथ ही स्टाफ क्वार्टर्स के लिए भी आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की जाये। श्री पटेल ने अधिकारियों को 2 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा है। बैठक में एमडी मंडी बोर्ड सुश्री प्रियंका दास मौजूद थी।

मंत्री श्री कमल पटेल ने मंडी बोर्ड में आयोजित बैठक में समस्त तकनीकी संभागीय यंत्रियों और कार्यपालन यंत्रियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मंडियों के आधुनिकीकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही और कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा। मंत्री श्री पटेल ने मॉडल मंडियों के मास्टर प्लान में विशेष रूप से एक जैसे गेट, रेस्ट हाउस, किसान क्लीनिक, बाउंड्री वॉल, शेड, कैंटीन, खाद–बीज और दवाई के लिए बाजार इत्यादि के पर्याप्त बंदोबस्त करने को कहा है।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि पूर्व में जारी निर्देशों का पालन करते हुए भारतीय परंपरा अनुसार किसानों का स्वागत–सत्कार किया जाये। शुद्ध पेयजल एवं किसान विश्राम गृह की व्यवस्था सुनिश्चित करें, मॉडल मंडियों के लिये चलित वाटर कूलर, किसान सभागार, किसान क्लीनिक, कृषि–यंत्रो के सर्विस सेंटर इत्यादि की भी व्यवस्था करें।

(पृष्ठ 1 का शेष)

## प्रदेश के कृषि उत्पाद देश ही नहीं दुनिया....

**समर्थन मूल्य से अधिक मिलने पर ही किसान बाजार में बेचें अपना उत्पाद**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। इस कड़ी में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोड मैप विकसित किया गया। अर्थ व्यवस्था और रोजगार इस रोड मैप के आधार हैं। प्रदेश के युवा और किसानों में क्षमता,प्रतिभा और योग्यता है। किसान उत्पादक संगठन कृषकों की एकता, पहल और प्रगति का प्रतीक बनेगें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यदि किसानों को समर्थन मूल्य से अधिक कीमत मिले तो ही वे अपना उत्पाद बाजार में बेचें। राज्य सरकार किसानों का एक– एक दाना खरीदेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सीमन प्रयोगशाला, किसान उत्पादक संगठन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना, मवेशियों के लिए यूनिक आईडी जैसी गतिविधियां प्रदेश में कृषि और पशुपालन का नया अध्याय लिखेंगी।

कार्यक्रम को पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल और किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने भी संबोधित किया। अपर मुख्यसचिव पशुपालन श्री जे.एन. कंसोटिया ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की।

**सीमन उत्पादन प्रयोगशाला**

भदभदा भोपाल में स्थापित सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोडक्शन फेसलिटी से उच्च अनुवांशिकता के देशी साण्डों जैसे गिर, साहीवाल, थारपारकर और भैंस की मुर्रा नस्लों का सेक्स सॉरटेड उत्पादन किया जा सकेगा। इसके उपयोग से 90 प्रतिशत बछिया ही पैदा होगी जिससे उच्च अनुवांशिक गुणवत्ता की मादाओं की बढ़ोतरी होने से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। बछड़ों के लालन–पालन में अनावश्यक व्यय की बचत होगी। निराश्रित पशुओं की संख्या को भी सीमित किया जा सकेगा।

**किसान उत्पादक संगठन (FPO)**

एफपीओ के गठन के लिए न्यूनतम 300 से 500 किसान सदस्यों को शामिल किया जाता है। प्रदेश के 418 एफपीओ विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों जैसे बीज उत्पादन, उपार्जन, प्रोसेसिंग,दूध उत्पादन,मुर्गी पालन, शहद उत्पादन और विपणन आदि कार्य कर रहे हैं। एग्रीक्लचर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की स्कीम से एफपीओ को लाभान्वित कराने का कार्य किया जा रहा है।

**एग्रीक्लचर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम में मध्यप्रदेश प्रथम**

इस योजना में कृषि से जुड़े उद्यमी, एफपीओ, स्टार्टअप, स्व–सहायता समूह इत्यादि जो भी लोग कृषि अद्योसंरचना निर्माण के लिए बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, उन्हें दो करोड़ की सीमा तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह वित्तीय सहायता कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चैन, वेअरहाउस, साइलो, पैक हाउस, ग्रेडिंग एवं पेकेजिंग यूनिट, लाजिस्टिक सुविधा, ई–राइपनिंग चेम्बर,आदि के लिए प्रदान की जा रही है। इस योजना में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।

**दो करोड़ 45 लाख गौ–भैंस वंशीय पशुओं को यूनिक आईडी देकर मध्यप्रदेश देश में प्रथम**

राज्य के मवेशियों का भी अब यूनिक आईडी होगा। योजना के तहत गौ–भैंस वंशीय पशुओं के कान में टैग लगाया जा रहा है। टैग पर बारह अंकों का आधार नम्बर अंकित है। जिसे इनॉफ साफ्टवेयर में अपडेट किया जा रहा है। साफ्टवेयर में मवेशियों का लेखा जोखा होगा। जो ऑनलाईन भी उपलब्ध होगा। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 45 लाख गौ–भैंस वंशीय पशुओं की टैगिंग की जा चुकी है। इस योजना में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।

## प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय तीन माह तक सप्ताह में पाँच दिन लगेंगे

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए, प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय आगामी तीन माह तक सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह में पाँच दिन लगेंगे। शनिवार एवं रविवार को कार्यालय बंद रहेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में 8 अप्रैल से प्रतिदिन आगामी आदेश तक प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा।

(पृष्ठ 2 का शेष)

## पथ विक्रेताओं के जीवन को....

कलेक्टर्स को भी जिला स्तर पर ऐसे हितग्राहियों से सम्पर्क कर उनके प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। बैंक स्तर पर आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये बैंकर्स से भी लगातार राज्य सरकार सम्पर्क कर रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन में केन्द्र से भी लगातार सहयोग मिल रहा है।

**ग्रामीण क्षेत्र में भी लाभान्वित हो रहे हितग्राही**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रति माह कलेक्टर्स–कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस में इस योजना की समीक्षा की जा रही है। जिला अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। प्रत्येक जिले में हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए अभियान संचालित कर परिणाम देने के निर्देश दिए गए हैं। बीते माह करीब 13 लाख आवेदन–पत्र मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ–विक्रेता ऋण योजना में प्राप्त हो चुके हैं। पोर्टल सक्रिय किये जाने से यह संख्या निरंतर बढ़ रही है। लगभग 2 लाख प्रकरण बैंकों को भेजे जा चुके हैं। इनमें से एक लाख प्रकरण मंजूर हो गये हैं और हितग्राहियों को अपने व्यवसाय के उन्नयन के लिए राशि प्राप्त हो चुकी हैं। गत 23 मार्च को राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 60 हजार ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 60 करोड़ रूपये की ऋण राशि उनके खातों में अंतरित की गई।

**शहरों में सबसे आगे जनजातीय बहुल क्षेत्र**

मध्यप्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा में अलीराजपुर 75 प्रतिशत, नैनपुर 70 और अमरवाड़ा नगर पालिका 67 प्रतिशत उपलब्धि के साथ प्रथम तीन शीर्ष नगरीय निकायों में शामिल हैं। अन्य तीन नगर परिषद जो इस योजना के क्रियान्वयन में आगे हैं उनमें सांवेर (जिला इंदौर) 87 प्रतिशत, माचलपुर (जिला राजगढ़) 84 प्रतिशत और निवाड़ी 80 प्रतिशत शामिल हैं।

(पृष्ठ 1 का शेष)

## पहली बार गेहूं के साथ चना.....

निश्चित ही इससे किसानों को न केवल लाभ होगा, बल्कि उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी सुनिश्चित होगा।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि किसानों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक जिले में किसान ओपीडी भी प्रारंभ की जायेगी। अभी हरदा और जबलपुर में कृषि ओपीडी संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिये मण्डियों को आधुनिक बनाया जा रहा है। मण्डियों में ही किसानों को खाद, बीज, दवाई और कृषि उपकरण किफायती दामों पर मिलने की व्यवस्था की जा रही है। किसानों को मण्डियों में कैंटीन सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी, जहाँ से वे किफायती दामों पर अन्य वस्तुएँ भी क्रय कर सकेंगे। प्रारंभिक तौर पर चिन्हित मण्डियों में पेट्रोल पम्प खोले जायेंगे, जिसे बाद में अन्य मण्डियों में विस्तारित किया जायेगा।

# नरेगा से देश में पहली बार निर्मित हो रहे हैं अनाज भण्डारण के लिए पक्के चबूतरे

### जिलों को 65 करोड़ 50 लाख रूपये जारी

**भोपाल।** खरीदी केन्द्रों पर अनाज की सुरक्षा एवं भण्डारण के मकसद से पक्का चबूतरा (ह्रच) का निर्माण देश में पहली बार महात्मा गांधी नरेगा से किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में खरीद समिति द्वारा चिन्हित केन्द्रों में पक्के चबूतरे के निर्माण के लिए जिलों को 65 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि मनरेगा से जारी की गई है। अभी तक 564 चबूतरों का निर्माण कर 6 लाख 94 हजार 500 मैट्रिक टन क्षमता का अनाज सुरक्षित रखा जा रहा है, वहीं 675 कार्य प्रगतिरत हैं। चबूतरा निर्माण कार्य में 8 करोड़ 60 लाख रूपए की मजदूरी का भुगतान ग्रामीणों को किया गया है, वहीं सामग्री पर 44 करोड़ रूपए का व्यय किया गया है। राज्य शासन का निरंतर प्रयास है कि अनाज का एक भी दाना असमय बारिश से खराब नहीं हो।

खरीदी केन्द्रों में मनरेगा अंतर्गत पक्का चबूतरा निर्माण होने से खरीदे गए अनाज को असमय बारिश से होने वाले नुकसान से सुरक्षा मिलेगी। ग्राम पंचायत की भूमि पर तय खरीदी केन्द्रों में चबूतरा निर्माण होने से खाद्यान उपार्जन समिति द्वारा चबूतरे के मासिक किराए का भुगतान ग्राम पंचायत को किया जाएगा। इस प्रकार मनरेगा के तहत स्थाई परिसम्पत्ती के निर्माण के साथ ही ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़ेगी। उल्लेखनीय है कि मनरेगा अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत कार्यों में देश में पहली बार अनाज भण्डारण के लिए संरचना निर्माण का प्रावधान किया गया है। राज्य में मार्कफेड द्वारा सुझाए गए डिजाईन के आधार पर चबूतरे का निर्माण मनरेगा से किया जा रहा है।

# आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की संजीवनी बनेगा प्रदेश का पर्यटन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प और साहसी निर्णयों ने आज मध्यप्रदेश को विकासशील राज्य की अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा किया है। उनके प्रयासों और संकल्प से आज पर्यटन क्षेत्र आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश की संजीवनी के रूप में उभरा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मध्यप्रदेश एक दूसरे के पूरक है।

नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य और अद्भुत स्थापत्य कला के धनी मध्यप्रदेश का गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति पूरे भारत में अद्वितीय है। जिस तरह हीरे की असली परख जौहरी को ही होती है उसी तरह मध्यप्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार और विकास की असीम संभावनाओं को तलाशने का हुनर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान में ही है। उन्होंने न सिर्फ प्रदेश के नैसर्गिक और लुभावने स्थलों को पर्यटन के लिए विकसित किया बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा किए। अब पर्यटन सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा बल्कि रोजगार, स्थानीय संस्कृति और खान–पान, कला और स्थापत्य कला का केंद्र–बिंदु भी बनके उभरा है।

**एडवेंचर टूरिज्म का हॉटस्पॉट मध्यप्रदेश**

मध्यप्रदेश एडवेंचर टूरिज्म का हॉटस्पॉट बनके उभरा है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और मनभावन वातावरण अनायास ही ट्रेकिंग, सफारी और कैंपिंग के शौकीनों को आकर्षित करता है। एडवेंचर टूरिज्म की इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन विभाग ने प्रदेशभर में 30 से ज्यादा कैंपिंग साइट विकसित किए गए हैं। पर्यटकों के हॉलिडे को ''एक्टिव हॉलिडे'' में परिवर्तित करते हुए टूर–डे सतपुड़ा, हेरिटेज रन, पचमढ़ी मॉनसून मैराथन जैसे कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की गई है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बैलून सफारी, टाइग्रेस ऑन ट्रेल और भोपाल में प्रदेश के पहले ड्राइव इन सिनेमा की स्थापना आदि प्रमुख नवाचार रहे हैं।

वर्तमान में भी मध्यप्रदेश को ''365 डेज का टूरिस्ट डेस्टिनेशन'' बनाने का संकल्प लेकर सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

# प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिये 10 छात्रावासों की मंजूरी

### प्रथम किश्त के रूप में मिली 26.25 करोड़ रूपये की राशि

**भोपाल।** प्रदेश में अनुसूचित–जाति वर्ग की छात्राओं के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिये केन्द्र सरकार की बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अन्तर्गत 10 जिलों में छात्रावास मंजूर हुए हैं। इनके लिये प्रथम किश्त के रूप में 26 करोड़ 25 लाख रूपये की राशि मंजूर हुई है। यह छात्रावास भवन केन्द्र सरकार की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मंजूर हुए हैं।

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2020–21 में बालिका छात्रावास के लिये 1750 सीट मंजूर की हैं। यह सीटें इंदौर, मुरैना, भिंड, उज्जैन, छतरपुर, आगर–मालवा, विदिशा, शाजापुर, सीहोर और देवास में मंजूर हुई हैं। केन्द्र सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालयों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में पढ़ रहे अनुसूचित–जाति वर्ग के बालक और बालिकाओं को छात्रावास सुविधा प्रदान करने के मकसद से बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना संचालित की जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा पहले चरण में इसके लिये 52 करोड़ 50 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं।

प्रदेश में 1750 सीटों के छात्रावास की स्वीकृति से प्रदेश में अनुसूचित–जाति वर्ग की बालिकाएँ छात्रावास योजना का लाभ लेकर उच्च अध्ययन कर सकेंगी। यह छात्रावास केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गहलोत के प्रयासों से मंजूर हुए हैं।

**छात्रावासों के लिये उत्कृष्टता पुरस्कार योजना**

अनुसूचित–जाति कल्याण विभाग द्वारा छात्रावासों के उत्कृष्ट संचालन एवं व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के मकसद से उत्कृष्टता पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है। योजना में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले छात्रावासों के प्रभारी एवं कर्मचारियों को 10 हजार रुपये का नगद पुरस्कार, शील्ड एवं प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया जा रहा है। चयनित छात्रावास के संचालकों को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर पुरस्कृत किया जा रहा है।

**छात्रावासों में पुस्तकालय योजना**

विभाग द्वारा प्रत्येक छात्रावास में विद्यार्थियों की सुविधा के लिये उनके पाठ्यक्रम से संबंधित जीवनोपयोगी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिये पुस्तकालय योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से करीब 85 हजार विद्यार्थियों को फायदा पहुँच रहा है।

# शिल्प एवं कला के संरक्षण से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता प्रदेश

''आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश'' की आत्मा ''वोकल फार लोकल'' में निहित है। आत्मा की इस आवाज पर ही स्थानीय शिल्प कला, संस्कृति में प्रदेश की पुरा–सम्पदा और हुनर को शामिल कर प्रदेश के आर्थिक विकास की नींव को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हुनरमंद हाथों से कराकर उन्हें बाजार मुहैया कराना ही ''वोकल फॉर लोकल'' है।

प्रदेश की परम्परागत शिल्प कला को उसी अंचल की पहचान बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ''एक जिला – एक उत्पाद'' जैसी अभिनव पहल की गई है। इस पहल के अंतर्गत प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और हस्तशिल्प विकास निगम स्थानीय शिल्प एवं कला का संरक्षण–संवर्धन का काम कर रहे हैं।

कुटीर और ग्रामोद्योग ग्रामीण अंचल में रोजगार के अवसरों के सृजन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रदेश सरकार परम्परागत ग्रामोद्योग के संरक्षण, संवर्धन एवं समग्र विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। राज्य सरकार उत्पादों की गुणवत्ता का विकास, उत्पादों को बाजारोन्मुखी बनाना, कारीगरों को कौशल विकास, उन्नत तकनीकी का प्रशिक्षण, आधुनिकता उपकरणों का प्रदाय तथा उत्पादों की विपणन सहायता उपलब्ध करा रही है। मेलों–प्रदर्शनियों के माध्यम से भी शिल्पियों को मार्केटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जा रहा है। पत्थर शिल्प, जरी, बेलमेटल, पेंटिंग और वस्त्र छपाई के शिल्पियों को उत्पादों/गुणवत्ता एवं मानकीकरण के लिये क्राफ्ट मार्क प्राप्त करने में सहायता की गई है। बुदनी में शिल्पियों को सुगमता से कच्चा माल सुलभ कराने के लिए खराद शिल्प का रॉ मटेरियल डिपो स्थापित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में हाथकरघा वस्त्र बुनाई की एक समृद्ध परम्परा है। प्रदेश की चंदेरी एवं महेश्वरी साड़ियाँ एवं वारासिवनी (बालाघाट), सौंसर (छिन्दवाड़ा), पढ़ाना–सारंगपुर (राजगढ़) के हाथकरघा वस्त्र अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। वस्त्रों की छपाई में बाग की ब्लाक–प्रिंट तथा भैरोगढ़ की बटिक–प्रिंट तारापुर के नांदना प्रिंट आदि प्रमुख है। पिछले वर्षों में व्यवसायिक वस्त्र उत्पादन प्रमुख रूप से चंदेरी, महेश्वर, इन्दौर, उज्जैन, सीहोर, वारासिवनी, सौंसर में किया जाता था तथा सीहोर, इन्दौर, ग्वालियर, मंदसौर, सारंगपुर, सौंसर आदि में शासकीय उत्पादन किया जाता था। अब रीवा, सागर, निवाड़ी, मण्डला, शहडोल में भी हस्तशिल्प निगम की हाथकरघा गतिविधियाँ आरंभ कराई गई हैं। हाथकरघा वस्त्र उत्पादन के अंतर्गत शासकीय वस्त्र उत्पादन एवं कॉमर्शियल हाथकरघा में 8 करोड़ 14 लाख रूपये का वस्त्र उत्पादन किया गया। रूपये 8 करोड़ 65 लाख का शासकीय वस्त्र, शासकीय विभागों को प्रदाय किया गया। इस कार्य में 1165 करघे संचालित रहे। योजना में 2 लाख 83 हजार मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया। राज्य सरकार का प्रयास है कि इस वर्ष 200 लाख रूपये के वस्त्रों का उत्पादन कर शासकीय विभागों को विक्रय किया जाए।

राज्य सरकार द्वारा इस वित्त वर्ष में दिसम्बर 2020 तक 09 प्रदर्शनी लगाई गई। हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा नागपुर (महाराष्ट्र) में मृगनयनी एम्पोरियम जनवरी में आरंभ किया गया। प्रदेश के 04 जिलों – बैतूल, होशंगाबाद, मण्डला, महेश्वर, सागर में स्थानीय शिल्पियों को मार्केटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए मृगनयनी के सेल्स काउंटर खोले गये हैं। इससे इन स्थानों के निवासियों को प्रदेश के हस्तशिल्प – हाथकरघा एक ही जगह पर उपलब्ध हो रहे हैं। प्रदेश के बाहर हस्तशिल्प विकास निगम का एकता मॉल, केवड़िया (गुजरात), रायपुर (छत्तीसगढ़) मुम्बई वाशी (महाराष्ट्र) तथा लेपाक्षी हैदराबाद (तेलंगाना) में एम्पोरियम और विक्रय काउंटर आरंभ हो चुके हैं।

# मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल में सड़कों पर निकलकर लोगों से मास्क लगाने की अपील की

**भाइयों, बहनों, मास्क लगाएँ और कोरोना को हराएँ ● मेरी सुरक्षा, मेरा मास्क ● मानवता जीतेगी कोरोना हारेगा**

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज सायं मास्क लगाने तथा कोरोना संबंधी सभी सावधानियों का पालन करने की जनता से अपील करने के लिए खुले वाहन में सवार होकर सड़कों पर निकले। उन्होंने स्थान–स्थान पर लोगों से कहा कि ''मैं आपका सेवक आपसे हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि कोरोना को हराने के लिए मास्क अवश्य लगाएँ, एक दूसरे के बीच सुरक्षित दूरी रखें तथा बार–बार हाथ धोएं एवं सैनिटाइज करें।'' श्री चौहान ने कहा कि– ''ऐसा करने के लिए अपने परिवार, संबंधियों एवं अन्य व्यक्तियों को प्रेरित करें। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क। मास्क लगाएँ और कोरोना को हराएँ। मानवता जीतेगी, कोरोना हारेगा।''

**कोरोना के विरुद्ध जन–अभियान में हर व्यक्ति शामिल हो**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह हमारा कर्त्तव्य एवं सामाजिक जिम्मेदारी है कि कोरोना के विरुद्ध अभियान में हर व्यक्ति शामिल हो। जन–जागरूकता एवं सभी के सक्रिय सहयोग से ही हम कोरोना को एक प्रभावी रूप से शीघ्र हरा पाएँगे। इस अभियान में स्वयं शामिल हों, अपने परिवार को शामिल करें तथा दूसरों को प्रेरित करें।

**मास्क नहीं तो बात नहीं, मास्क नहीं तो सामान नहीं**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए दो महत्वपूर्ण कार्य करें ''मास्क नहीं तो बात नहीं'', ''मास्क नहीं तो सामान नहीं।'' आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात न करें जो मास्क न लगाए हो। यदि आप सामान लेने बाजार जाते हैं और दुकानदार ने मास्क नहीं लगाया है तो आप उस दुकानदार से सामान न खरीदें। ऐसे ही यदि आपकी दुकान पर कोई सामान लेने आता है और उसने मास्क नहीं लगाया है तो उसे सामान देने से इंकार कर दें।

**संकट बड़ा है, पूरी सावधानी रखें**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हमने कोरोना की जाँच, उपचार आदि की पूरी व्यवस्था अस्पतालों में की हैं। परंतु हम चाहते हैं कि कोरोना का संक्रमण फैले ही नहीं। इसके लिए आवश्यक है कि आप सभी मास्क लगाने जैसी सभी सावधानियों का पालन करें।

**लॉकडाउन उपाय नहीं**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लॉक डाउन करने से अर्थ–व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। लोगों के काम–धंधे चौपट हो जाते हैं। लोगों की रोजी–रोटी छिन जाती है। अतः हम लॉक डाउन नहीं लगाना चाहते। हम चाहते हैं कि हम सब पूरी सावधानियाँ बरतें और कोरोना को हराएं।

**मैंने अपनी पत्नी, बच्चों को मास्क लगाया, आप भी लगाएं**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के विरुद्ध अभियान की अपने घर से ही शुरुआत करें। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को स्वयं मास्क लगाया है। आप भी अपनी पत्नी, बच्चों एवं परिवारजनों को मास्क लगाएँ तथा दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान इस दौरान आनंद नगर, गांधी मार्केट, पिपलानी, गांधी चौराहा, बरखेड़ा स्थित विजय मार्केट, महाराणा प्रताप नगर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, 6 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर मार्केट, विट्टन मार्केट, रविशंकर मार्केट, शिवाजी नगर, पंचशील नगर, हर्षवर्धन नगर, माता मंदिर चौराहा, न्यू मार्केट, रोशनपुरा चौराहा आदि बाजारों में गये और आम नागरिकों को समझाइश देकर कोरोना के विरूद्ध अभियान में सहयोग का अनुरोध किया।

## पंचायत सचिव ग्रामीण विकास का आधार : डॉ. मिश्रा

**भोपाल।** ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की कल्याणकारी एवं हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी आम व्यक्ति तक पहुँचाने और उसका लाभ दिलाने में पंचायत सचिवों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा शुक्रवार को दतिया में मध्यप्रदेश पंचायत संगठन दतिया द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव ही ग्रामीण विकास का आधार है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिनेशचंद्र शर्मा ने की। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि पंचायत सचिव ग्रामीण जनता से सीधे संपर्क में रहते हैं। उनसे जनता को सहयोग की अपेक्षा रहती हैं। डा. मिश्रा ने समझाईश दी कि पंचायत सचिव जनता के साथ पूरे संयम एवं गंभीरता के साथ बातचीत करें। अपने कार्य के दौरान वाणी एवं शब्दों पर भी नियंत्रण रखें। ग्रामीणों से मधुर एवं सदभाव पूर्वक व्यवहार कर उनकी समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों की कार्यशैली से जनता ने महसूस करना चाहिए कि आप उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए उनकी सेवा कर रहे हैं।

## दीनदयाल अंत्योदय योजना नवगठित 29 नगरीय निकायों में भी होगी लागू

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग से हुई मंत्रि–परिषद की बैठक में दीनदयाल अंत्योदय योजना–शहरी आजीविका (डे–एनयूएलएम) का प्रदेश की 378 नगरीय निकायों से विस्तार करते हुए, नवगठित 29 नगरीय निकायों में भी लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

**विकास निधि की व्यवस्था :** मंत्रि–परिषद ने राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, चिड़ियाघरों के लिए राज्य शासन के आदेश 9 जुलाई 2008 द्वारा गठित विकास निधि की व्यवस्था के संबंध में वित्त विभाग एवं गाइडलाइन अनुसार निर्णय लेने का अनुमोदन किया।

**सातवां वेतनमान एवं कैरियर संवर्धन स्कीम :** मंत्रि–परिषद ने तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत इंजीनियरिंग एवं पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को भारत सरकार के राजपत्र एक मार्च 2019 में प्रकाशित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुशंसित सातवां वेतनमान एवं कैरियर संवर्धन स्कीम का लाभ विशेष भत्तों को छोड़कर एक जनवरी 2016 से देने का अनुमोदन किया।

**वाणिज्यिक कर विभाग :** मंत्रि–परिषद ने वाणिज्यिक कर विभाग की वार्ड नं. 22 अम्बेडकर चौक, जिला बालाघाट स्थित परिसम्पत्ति के निर्वर्तन के लिए एच–1 निविदाकार की उच्चतम निविदा मूल्य राशि 8 करोड़ 80 लाख रूपये का अनुमोदन करते हुए निविदाकार द्वारा निविदा मूल्य राशि 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा करने का निर्णय लिया गया।

**अस्थाई पद :** मंत्रि–परिषद ने मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड के लिए सृजित 18 अस्थाई पदों को एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी

डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।